A–0852

Total Pages : 6 **Roll No. ....**

CRTI-103/DRTI-103

Certificate/Diploma in Right to Information (CRTI/DRTI)

Judiciary and Important Legislatures Effecting RTI

Examination February, 2026

Time : 2:00 Hrs. Max. Marks : 100

Note* :–** This paper is of Hundred (100) marks divided into Two (02) Sections 'A' and 'B'. Attempt the questions contained in these Sections according to the detailed instructions given therein. ***Candidates should limit their answers to the questions on the given answer sheet. No additional (B) answer sheet will be issued.

नोट :– यह प्रश्न–पत्र सौ (100) अंकों का है, जो दो (02) खण्डों 'क' तथा 'ख' में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है। ***परीक्षार्थी अपने प्रश्नों के उत्तर दी गई उत्तर-पुस्तिका तक ही सीमित रखें। कोई अतिरिक्त (बी) उत्तर-पुस्तिका जारी नहीं की जायेगी।***

Section–A

(खण्ड–क)

Long Answer Type Questions

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न) (2×26=52)

***Note* :–** Section 'A' contains Five (05) Long-answer type questions of Twenty Six (26) marks each. Learners are required to answer any *two* (02) questions only.

नोट :– खण्ड 'क' में पाँच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए छब्बीस (26) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल **दो** (02) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. Explain the role of the Indian Judiciary in strengthening the Right to Information (RTI). Discuss how various judgments have helped shape the present legal framework of RTI.

   भारतीय न्यायपालिका की सूचना के अधिकार (RTI) को मजबूत करने में क्या भूमिका है ? विभिन्न न्यायिक निर्णयों ने RTI के वर्तमान कानूनी ढांचे को कैसे आकार दिया, स्पष्ट कीजिए।

2. Discuss the constitutional position of RTI in India with reference to Article 19(l)(a). How has the Supreme Court interpreted RTI as a fundamental right ?

भारत में RTI की संवैधानिक स्थिति का अनुच्छेद 19(1)(क) के संदर्भ में विश्लेषण कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने RTI को मौलिक अधिकार के रूप में कैसे व्याख्याति किया है ?

3. Examine the various laws, schemes, and guidelines aimed at protecting RTI activists in India. Highlight the challenges that still remain in ensuring their safety.

भारत में RTI कार्यकर्ताओं के सुरक्षा के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों, योजनाओं और दिशानिर्देशों की विवेचना कीजिए। उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में अभी भी मौजूद चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।

4. Describe at least five landmark judicial propositions or decisions that significantly influenced the interpretation and implementation of the RTI Act, 2005.

RTI अधिनियम, 2005 की व्याख्या और कार्यान्वयन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने वाले कम से कम पाँच ऐतिहासिक न्यायिक सिद्धान्तों या निर्णयों का वर्णन कीजिए।

5. Analyse the impact of significant legislations such as the IT Act 2000, Whistle Blowers Protection Act 2014, and Lokpal and Lokayuktas Act 2013 on the functioning and effectiveness of RTI.

IT अधिनियम, 2000, व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 जैसे प्रमुख विधियों का RTI के कार्य और प्रभावशीलता पर क्या प्रभाव पड़ा है, विश्लेषण कीजिए।

Section–B

(खण्ड–ख)

Short Answer Type Questions

(लघु उत्तरीय प्रश्न) (4×12=48)

***Note* :–** Section 'B' contains Eight (08) Short-answer type questions of Twelve (12) marks each. Learners are required to answer any *four* (04) questions only.

नोट :– खण्ड 'ख' में आठ (08) लघु उत्तरीय प्रश्न दिये गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए बारह (12) अंक निर्धारित हैं। शिक्षार्थियों को इनमें से केवल **चार** (04) प्रश्नों के उत्तर देने हैं।

1. What role has the judiciary played in protecting the Right to Information in India ?

   भारत में सूचना के अधिकार की सुरक्षा में न्यायपालिका की क्या भूमिका रही है ?

2. How does Article 19(l)(a) support the citizen's right to information ?

   अनुच्छेद 19(1)(a) नागरिकों के सूचना के अधिकार का समर्थन कैसे करता है ?

3. Which landmark case recognized access to information as a fundamental right under the Constitution ?

   कौन-सा महत्वपूर्ण न्यायिक मामला सूचना तक पहुँच को मौलिक अधिकार मानता है ?

4. What legal protections are available for RTI activists facing threats or harassment ?

   खतरे या उत्पीड़न का सामना करने वाले RTI कार्यकर्ताओं के लिए कौन-सी कानूनी सुरक्षा है ?

5. How do courts interpret exemptions under Section 8 of the RTI Act ?

   न्यायालय RTI अधिनियम की धारा 8 में दी गई अपवादों की व्याख्या कैसे करते हैं ?

6. What judicial proposition emerged from the Union of India *Vs.* Association for Democratic Reforms case ?

यूनियन ऑफ इण्डिया **बनाम** एशोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले से कौन-सा न्यायिक सिद्धान्त सामने आया ?

7. Which legislations influence the scope of the RTI Act, 2005 ?

कौन-कौन से कानून RTI अधिनियम, 2005 के दायरे को प्रभावित करते हैं ?

8. How has the judiciary enforced transparency when public authorities deny information ?

जब सरकारी संस्थान सूचना देने से इंकार करते हैं, तब न्यायपालिका पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित् करती है ?

****